



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2026

फाल्गुन 6, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 56 / 79-वि-1-2026-1-क-3-2026

लखनऊ, 25 फरवरी, 2026

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 जिससे नगर विकास अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 फरवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 2 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 115 का संशोधन निरसन और व्यावृत्ति	2-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 115 के खण्ड (i) में, शब्द और प्रतीक "कुष्ठाश्रम" निकाल दिये जायेंगे।
	3-(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2026 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959), उत्तर प्रदेश राज्य के कतिपय नगरों के लिए ऐसे नगरों के बेहतर नगर पालिका शासन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से नगर निगमों की स्थापना हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या-83/2010 फेडरेशन ऑफ लेप्रोसी ऑर्गनाइजेशन (फोलो) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या-1151/2017 विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी बनाम भारत संघ और अन्य में, अपने आदेश दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से राज्यों को कुष्ठ रोग से प्रभावित या ठीक हुए व्यक्तियों के विरुद्ध विभेद करने वाली और/या उनके प्रति अनादरसूचक विधियों को परिलक्षित करने के लिए एक समिति गठित करने हेतु निर्दिष्ट किया है और उनसे ऐसे विभेदकारी उपबंधों को हटाने के लिए अत्यावश्यक उपचारी कार्रवाई करने को कहा है।

पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा राज्य में प्रचलित उन विधियों को परिलक्षित किया गया जिनमें कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और/या कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के सम्बंध में विभेदकारी उपबंध थे, और ऐसे परिलक्षित विधिक उपबंधों में उपयुक्त संशोधन की मांग की गई। उपर्युक्त के दृष्टिगत पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 115 का संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 56(2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-3-2026

Dated Lucknow, February 25, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2026. The Nagar Vikas Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)
ACT, 2026

(U.P. ACT NO. 15 OF 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2026 . Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd day of February, 2026.

2. In clause (i) of Section 115 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the words and symbol "leper homes," shall be *omitted*. Amendment of Section 115 of U.P. Act no. 2 of 1959

Repeal and saving

3.(1) The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2026 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 3 of 2026

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) has been enacted to provide for the establishment of municipal corporations for certain cities in the State of Uttar Pradesh with a view to ensure better municipal governance of such cities.

The Hon'ble Supreme Court *vide* its order dated 07.05.2025 in Writ Petition (Civil) no. 83/2010 Federation of Lepy. Organ (Folo) & Anr. *versus* Union of India & Others and Writ Petition (Civil) no. 1151/2017 Vidhi Centre for Legal Policy *versus* Union of India & Others, directed the States to form a Committee to identify laws which discriminate against and/or are derogatory towards leprosy-affected or cured persons, and urged them to take urgent remedial action to remove such discriminatory provisions.

In order to ensure compliance of the aforesaid order, laws prevalent in the State which have discriminatory provisions in relation to persons affected by leprosy and/or persons cured of leprosy were identified by the Committee constituted for the aforesaid purpose and suitable amendments were sought in such identified legal provisions. In view of the above, it was decided to amend Section 115 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 3 of 2026) was promulgated by the Governor on 2nd February, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.